>

Title: Need to ensure the supply of coal to the power plants in the country.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि देश में कोयले की कमी है और इसकी वजह से देश के सभी राज्यों में जितने भी बिजली बोर्ड्स हैं, जहां बिजली का निर्माण होता है, उन सभी बोर्ड्स को कोयले की आपूर्ति में कमी हो गयी है जिसकी वजह से बिजली का निर्माण कम हो रहा है। ऐसी स्थिति होते हुए भी कोल मंत्रालय तथा सीआईएल द्वारा कोयले की ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी की जा रही है। यह बहुत गलत है। आज देश में कोयला मंत्रालय और सीआईएल, देश के सभी उद्योगों को कोयला आपूर्ति करती हैं। यह सब कुछ जानते हुए कि हमारे यहां 52 मीट्रिक टन कोयले की कमी है, कोयला मंत्रालय द्वारा ई-आक्शन किया जाता है, जिसमें ट्रेडर्स को कोयला दिया जाता है। जिन उद्योगों को कोयले की जरूरत है, उनको कोयला नहीं दिया जाता है। कोल कंजम्प्शन इंडस्ट्री को कोयला न देने के कारण, मैं मानता हूं कि ई-ऑक्शन के द्वारा सीधे-सीधे कोयले को ब्लैक करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि देश में बिजली की कमी है। सभी कोल-बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को 100 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति करें। साथ ही, लघु उद्योगों पर भी इसका परिणाम हो रहा है। ई-ऑक्शन के माध्यम से कोयले की कालाबजारी को कोल मंत्रालय द्वारा जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको रोकने के लिए ई-ऑक्शन प्रणाली तुंत रोकी जाए और जिन्होंने कोयले की मांग की हो, केवल उन्हीं को कोयला दिया जाए।